

फरीदाबाद मजदूर समाचार

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

मजदूर आन्दोलन

की

एक झलक

200 पेज, 50 रुपये

नई सीरीज नम्बर 67

जनवरी 1994

1/-

मजदूरों से थोड़ी गम्भीर गप-शप

पिछले साल इस समय दुनियाँ-भर से हिंसा-आतंक-उन्माद-हताशा की खबरें इस कदर आ रही थी आया हमारी रग-रग कट कर बाहर आ रही हो और जिन्दगी की अर्थहीनता पूर्ण हो गई हो। इससे भी खतरनाक थे विशेषज्ञों के वे विश्लेषण जो पांडित्यपूर्ण भाषा में इसे हम सब का अनन्त भविष्य घोषित कर रहे थे।

विदूषक : जरा ठहरो दोस्त

हवाई जहाज कमाल की चीज है

थोड़े दिनों में ही मैं

कई देश घूम आया हूँ

बैठो, और सुनो वहाँ का हाल-चाल :

बरसों बाद मैंने कम्पन सुनी है

जगह-जगह देखी है

हलचल मजदूरों की

अलग-थलग और छुट-पुट होते मजदूरों के आन्दोलनों में 1993 में इस पैमाने पर वृद्धि हुई है कि विश्वव्यापी मजदूर वर्ग के आन्दोलन की धुंधली-धुंधली आकृति नजर आने लगी है। इसने मजदूरों के हितों पर विभिन्न प्रकार की और विभिन्न स्तर की चर्चा को जन्म दिया है। इस विचार-विमर्श में अधिक से अधिक मजदूरों की भागीदारी मजदूर हितों को स्पष्टता देगी, उन्हें फोकस में लायेगी।

कार्यस्थल पर मजदूरों के हित चार धुरियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं : वेतन, वर्क लोड, वर्किंग कन्डीशन और सर्विस की सुरक्षा। यहां हम अलग-अलग से थोड़ा परख कर देखेंगे कि क्या-क्या चीजें इन्हें प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती हैं।

वेतन : एग्रीमेंटों में निर्धारित शर्तें पूरी करते हुये जितने समय काम किया जाता है उसके लिये मजदूर को दिये जाने वाले भुगतान को वेतन कहते हैं। बहुत से वरकरों को ऐसी एग्रीमेंटों के बिना काम करना पड़ता है और उन्हें टेकेदार या भेनेजमेंट के लिये पाँच सौ-सात सौ रुपये महीने पर काम करने को राजी होना पड़ता है — पाँच-सात सौ उनका वेतन हुआ। फरीदाबाद में ही फैक्ट्री मजदूर 400 रुपये से 4000 रुपये महीना वेतन पाते हैं। मजदूरों की सूझ-बूझ, संगठित ताकत और उन द्वारा किये जाते संघर्ष उनके वेतन के स्तर को काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। बेरोजगारों की तादाद और फैक्ट्री की आर्थिक स्थिति मजदूरों के वेतन पर उल्लेखनीय असर डालते हैं।

“काम के लेंगे पूरे दाम” का मतलब क्या है? क्या मजदूर जितने का काम करते हैं उतना वेतन पाते हैं? इधर-उधर बिखरे भेनेजमेंटों के आँकड़ों से एक मोटा-मोटी हिसाब लगा कर हम कह सकते हैं कि आज एक फैक्ट्री मजदूर औसतन महीने में दो-तीन लाख रुपये का उत्पादन करता है। ऐसे में इंडियन एयरलाइन्स पायलट का 25 हजार रुपये महीना वेतन भी उनके काम के पूरे दाम से कितना कम है इसका हिसाब आप स्वयं लगायें!

एग्रीमेंट के बाहर कौन-कौन सी चीजें हैं जो वेतन को सतत कुतरती रहती हैं? प्रमुख हैं : सरकार के पुलिस-फौज पर बढ़ते और स्वास्थ्य-शिक्षा-परिवहन पर घटते खर्च; बढ़ते टैक्स और रिजर्व बैंक से बढ़ती तादाद में नोट जारी करवा कर रुपये की क्रय-शक्ति घटा कर सरकार द्वारा लोगों से उनका धन हड़पने की स्कीम।

वर्क लोड : एक निश्चित समय में वरकर को कितना उत्पादन करना है इसे वर्क लोड कहते हैं। यहां भी वेतन के मामले की ही तरह एग्रीमेंट वाले और बिना एग्रीमेंट वाले वरकरों की दो कैटेगोरियाँ हैं। मशीनों का विकास वर्क लोड को कम करना सम्भव बनाता है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि मशीनें रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ वर्क की तीव्रता-तीखापन बढ़ाती हैं।

देहात से आते वरकरों को पहले-पहल लगता है कि फैक्ट्री में वरकरों के मजे हैं, कोई काम ही नहीं है। पाँच साल बाद वही वरकर जब आईना देखते हैं तो धँसी आँखें,

उभरी हड्डियाँ और उड़ते-सफेद होते बाल उन्हें नजर आते हैं। काम की तीव्रता उनके चेहरों में अपनी झलक दिखाती है।

नरम हो चाहे गरम, काली हो चाहे गोरी, फीजी हो चाहे सिविल, आस्तिक हो चाहे नास्तिक, लिमिटेड हो चाहे सरकारी, भेनेजमेंट कैसी भी क्यों न हो, प्रतियोगी, अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतियोगी बने रहने की अनिवार्यता उसे मजदूरों पर वर्क लोड में सतत वृद्धि करने को मजबूर करती है। सब भेनेजमेंटों का नारा है : “उत्पादन बढ़ाओ या तबाह हो!”, लेकिन मजदूरों की निगाह से देखें तो वास्तव में यह नारा कहता है, “मजदूरों, उत्पादन बढ़ाओ और तबाह हो!”

वर्किंग कन्डीशन : कहीं धूल-धुँआ, कहीं गैसों, कहीं हैमरों का शोर, कहीं आँखों में गिरता कचरा, कहीं शरीर को भेदती अदृश्य किरणें और कहीं सुपरवाइजरों की तीखी नजरें तो कहीं पीस रेट की दौड़ मजदूरों की वर्किंग कन्डीशनों का निर्माण करते हैं।

मजदूरों की जिन्दगी का यह महत्वपूर्ण पहलू भेनेजमेंटों की खर्च कम करने की नीति से मुख्यतः प्रभावित होता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति मजदूरों की लापरवाही में भेनेजमेंट की लापरवाही जुड़ कर वर्किंग कन्डीशन को बद से बदतर बनाती है।

सर्विस की सुरक्षा : वेतन, वर्क लोड, वर्किंग कन्डीशनों से भी महत्वपूर्ण मजदूरों के लिये उनकी सर्विस की सुरक्षा है। नौकरी से निकालने की शक्ति मजदूरों पर नियंत्रण जमाये रखने का भेनेजमेंटों के हाथों में प्रमुख औज़ार है।

वर्क लोड बढ़ा कर और नई मशीनरी स्थापित कर कम मजदूरों से पहले जितना प्रोडक्शन लिया जा सकता है। यह हर भेनेजमेंट जानती है और निरन्तर इसके लिये कोशिश करती है। न चाहते हुये भी इन्सैन्टिव स्कीमों के चक्कर में आ कर मजदूर उत्पादन बढ़ाते हैं, भेनेजमेंटों को ऐसी कार्रवाई के लिये लगातार नये-नये मौके देते हैं।

उत्पादन की हर शाखा में दुनियां में आज जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उससे कम उत्पादन किया जाता है। यह मंडी में मांग की वजह से होता है। पर मंडी की यह वास्तविकता अलग-अलग फैक्ट्रियों की भेनेजमेंटों के बीच होड़ को बढ़ा देती है। और फिर, बढ़ता उत्पादन प्रतियोगिता में तीखापन लाता जा रहा है। इस सब का अनिवार्य परिणाम होड़ में पिछड़ती जाती फैक्ट्रियों के बन्द होने में निकलता है और जो बची रहती हैं उनमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने की होड़ बढ़ती जाती है। छँटनी इसका लाजिमी नतीजा होता है और मजदूरों की सर्विस की सुरक्षा के लिये यह आज सबसे बड़ा खतरा बन गया है।

विदूषक : बाह! संकट-संकट-संकट

संकट जमीन पर, संकट आसमों में

संकट हवा में, हवा में है संकट

जूट में संकट, स्टील का संकट

तेल का संकट, एयरलाइन्स में संकट

बजारों में संकट, रेलों का संकट

बैंकों का संकट, उद्योगों में संकट, कृषि का संकट

शिक्षा में संकट, संस्कृति का संकट, नैतिकता का संकट . . .

संकट में जीवन

लीडर के भाषण में संकट, बेयरमैन-एम डी की बातों में संकट

मंत्रालय की रिपोर्टों में संकट, मंत्री की अपीलों में संकट

आई एम एफ के विश्लेषणों में संकट, आई एम एफ की हिदायतों से संकट

संकट में वर्ल्ड बैंक के कर्ज, वर्ल्ड बैंक के कर्जों से संकट

प्राय्वेट का संकट, सरकारी में संकट

बाम में संकट, दक्षिण का संकट

रेडियो-टीवी पे बहसों, अखबारों में बहसों

बहसों में संकट, संकट में बहसों

संकट-संकट-संकट

मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता

यह सही है कि संकट एक हकीकत है। यह भी सही है कि संकट के कारण मजदूरों पर चोतरफा हमले बढ़ते जा रहे हैं। वेतन में कटौती, वर्क लोड में वृद्धि, बदतर होती वर्किंग कन्डीशन और सपना बनती जा रही सर्विस की सुरक्षा आज सब क्षेत्रों में और दुनियाँ के हर इलाके की मुंह बोलती तस्वीर है। लेकिन यह संकट है क्या बला? हर मैनेजमेंट और सब सरकारें तथा आई एम एफ-वर्ल्ड बैंक जिस संकट-संकट की रट लगाये हैं वह दरअसल मजदूरी-प्रथा को बनाये रखने में उन्हें दरपेश बढ़ती दिक्कतें हैं। मजदूरी-प्रथा और मंडी में बिक्री के लिये उत्पादन का निकट का रिश्ता है। नित नई मशीनों का अविष्कार करते मानवों ने मानव श्रम की उत्पादकता इस कदर बढ़ा ली है कि आज उत्पादन की हर शाखा में प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी अधिक हो गई है कि क्षमता के अनुसार उत्पादन किया जाये तो मंडी में चीजें बिक ही नहीं सकती। इस वजह से कम्पनियों और देशों के बीच अपने-अपने माल को बेचने की होड़ बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में उत्पादन की कैपेसिटी में भी सतत इजाफा होता है और मंडी में प्रतियोगिता तीव्र-हिंसक-घातक होती जाती है। और, यह मजदूरों के लिये एक बेहतरीन भविष्य की सम्भावना भी लिये है। मजदूर बनना, मजदूरी करना एक मजबूरी होती है। मजदूरी-प्रथा का बढ़ता संकट मजदूरी-प्रथा के उन्मूलन के लिये परिस्थितियों प्रदान कर रहा है। मैनेजमेंटों और सरकारों के हमलों से जगह-जगह जूझ रहे मजदूर चीजों को थोड़ा और कुरेद कर देखें, थोड़ा और सोचें-समझें तो आज आसानी से दुनियाँ के पैमाने पर आपस में तालमेल कायम कर सकते हैं। साधनों को देखते हुये सामुहिक कदम उठा कर पृथ्वी से मजदूरी-प्रथा को समाप्त कर सकना अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है।

★ ★ ★

मजदूरों और मैनेजमेंटों के बीच संघर्ष और सम्वाद की धुरियाँ : एग्रीमेंटें, तालाबन्दियाँ और हड़तालें।

एग्रीमेंट : अपने नियन्त्रण को पुष्टा करने के लिये मैनेजमेंटें तीन साला एग्रीमेंटें करती हैं। प्रोडक्शन टारगेट, वर्क लोड, वर्किंग कन्डीशन, वेतन व सहूलियतें, डिडिलिजेंस, एग्रीमेंट लागू रहने के दौरान आर्थिक मांग उठाने पर पाबन्दी : यह सब मिल कर एग्रीमेंट की विषयवस्तु बनते हैं। और :

- एग्रीमेंट पर मजदूरों की राय लेने के वक्त आमतौर पर पूरी एग्रीमेंट मजदूरों को नहीं बताई जाती।

- एग्रीमेंट के अखरने वाले पहलू आमतौर पर मजदूरों की राय लेते वक्त छिपा लिये जाते हैं। कई बार सरासर झूठी बातें बताई जाती हैं।

- कई बार गोल-माल शब्दों का इस्तेमाल करके अखरने वाली बातें बता दी जाती हैं। 1989 में झालानी टूल्स में चार घन्टे के गोल-माल शब्द वाली एग्रीमेंट की एक झलक देखिये : “मजदूरों द्वारा आठ घन्टे काम करने को चार घन्टों का प्रोडक्शन माना जायेगा। भेटेरियल देने और बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं होगी। प्रत्येक मजदूर को किसी भी मशीन, किसी भी जॉब, किसी भी काम पर लगाया जा सकता है।” और एग्रीमेंट में निर्धारित घन्टे पूरे नहीं करने के नाम पर मजदूरों के वेतन में कटौती का सिलसिला शुरू किया हुआ है।

- एग्रीमेंटें आमतौर पर अंग्रेजी में की जाती हैं।

- एग्रीमेंट पर मजदूरों से हाथ उठाने को कहने से पहले तो मजदूरों को एग्रीमेंट की प्रतियाँ दी ही नहीं जाती, एग्रीमेंट पर दस्तखत के बाद भी उसकी प्रति मजदूरों की पहुँच से दूर रखी जाती है।

आमतौर पर मजदूर अपने को एग्रीमेंट में पैसों के मामले तक ही सीमित रखते हैं। पर पैसों के मामले में भी वेतन को लगातार कुतर रहे अप्रत्यक्ष प्रभावों को मजदूर नजरअन्दाज करते हैं। वर्क लोड के मामले में मजदूरों ने इधर कुछ आवाज उठानी शुरू की है पर “कुछ पाने के लिये कुछ खोना पड़ता ही है” की दलीलें कारगर रहती हैं। वर्किंग कन्डीशनों और सर्विस की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एग्रीमेंटों के वक्त मजदूर आमतौर पर चुप रहते हैं। मजदूरों का सामान्य रूख होता है कि “इतना जान कर क्या करेंगे, हमें कौनसी लीडरी करनी है।”

तालाबन्दी : मजदूर जब मैनेजमेंट के नियन्त्रण से बाहर हो जाते हैं अथवा जब मैनेजमेंट को मजदूरों पर कोई बड़ी चोट करनी होती है तब अक्सर मैनेजमेंटें फैक्ट्री में प्रोडक्शन बन्द कर देती हैं, लॉक आउट कर देती हैं। बड़े पैमाने पर आज मैनेजमेंटों का धारदार हथियार बनी तालाबन्दी हाल ही की उपज है।

उत्पादन ठप्प करना मजदूरों का फैक्ट्री के कर्ता-धर्ताओं के खिलाफ एक कारगर औजार रहा है। पर आज प्रोडक्शन रोक देना मैनेजमेंटों के हाथ में मजदूरों के खिलाफ धारदार हथियार बन गया है क्योंकि अब फैक्ट्रियों का संचालन कर रहे लोगों का फैक्ट्रियों में निजी पैसा बहुत कम लगा होता है इसलिये प्रोडक्शन बन्द रहने पर उन्हें

कोई विशेष निजी नुकसान नहीं होता और इसके जरिये वह मजदूरों पर अपना नियन्त्रण पुष्टा कर सकते हैं।

तालाबन्दी के घटनाक्रम पर चर्चा लॉक आउट की नब्ज पहचानने में मदद करेगी :

- आमतौर पर तालाबन्दी वेतन देने से पहले की जाती है।

- आमतौर पर तालाबन्दी के खिलाफ आवेदन-झापन का सिलसिला चलता है।

- आमतौर पर फैक्ट्री गेट पर धरना चलता है।

- आरम्भ में सब मजदूर फैक्ट्री गेट पर आते हैं। इधर-उधर खड़े हो कर बड़ाई में किसी को महाबली तो भर्त्सना में किसी को चूहा बनाते हैं।

- बड़ी संख्या में मजदूरों का फैक्ट्री गेट पर आने का सिलसिला कुछ दिन चलता है पर सब एक समय पर आने की बजाय दिन-भर आते-जाते रहते हैं।

- 15-20 दिन बाद धरने पर 10-15 लोग ही रह जाते हैं और अन्य मजदूर जब-तब फैक्ट्री गेट पर आ कर देख जाते हैं।

- खर्च बचाने के लिये बहुत से मजदूर अपने परिवारों को गांवों में भेज देते हैं। खर्च चलाने के लिये मजदूर अन्य जगह पर नौकरी, रेहड़ी-फेरी लगाने लग जाते हैं।

- महीने में एक-दो बड़ी मीटिंग फैक्ट्री गेट पर अथवा अन्य किसी स्थान पर।

- समय के साथ लॉकआउट फैक्ट्री के मजदूर बिखर जाते हैं।

- तालाबन्दी के दो-चार महीने बाद मजदूरों के बीच एक आम राय सी उभरती है कि किसी भी शर्त पर फैक्ट्री खुलवाई जाये।

- इस प्रकार मैनेजमेंट की शर्तें थोपी-स्वीकार की जाती हैं।

परम्परागत हड़ताल : मजदूरों की किसी जरूरत अथवा मैनेजमेंट की किसी मांग की वजह से हड़तालें होती हैं। हड़ताल में फैक्ट्री का चक्का जाम होता है। मैनेजमेंट के गुन्डों, पुलिस और हड़ताल-तोड़कों से मजदूरों का अक्सर टकराव होता है। मजदूरों को गिरफ्तार करवाया जाता है और थानों में पुलिस उनकी पिटाई करती है। मजदूरों पर गम्भीर आरोप लगा कर कइयों को जेल में बन्द कर दिया जाता है और अदालतें जमानत पर रिहा करने से इनकार करती हैं। और ऐसी जुझारू परम्परागत हड़तालें भी आमतौर पर फेल हो रही हैं।

इन हड़तालों के फेल होने का प्रमुख कारण आमतौर पर उनका एक फैक्ट्री के दायरे में सीमित होना होता है।

यह तो हुई जुझारू संघर्ष की बात। जबकि, आमतौर पर हड़तालें और आन्दोलन आजकल रस्मी अथवा फर्जी किस्म के होते हैं।

रस्मी : संगठन और लीडर अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिये जो हड़तालें करवाते हैं वे रस्मी होती हैं। रस्मी हड़तालें आमतौर पर एक दिन की होती हैं।

फर्जी : अपनी जरूरत के लिये मैनेजमेंटें जो हड़तालें करवाती हैं वह फर्जी हड़तालें होती हैं। उदाहरण के लिये जून 1991 में केल्विनेटर मैनेजमेंट ने जब तालाबन्दी की हुई थी तब केल्विनेटर को पार्ट्स सप्लाई करने वाली स्टेरीवियर फैक्ट्री में जूते-वर्दी के लिये की गई हड़ताल फर्जी हड़ताल थी।

★ ★ ★

एग्रीमेंटों, तालाबन्दियों और परम्परागत हड़तालों में आमतौर पर मजदूरों का नुकसान ही होता है। हमारे मूल्यांकन के अनुसार इसके तीन बुनियादी कारण हैं : 1) सोचने, फैसले लेने और आदेश देने की प्रक्रिया का एक छोटे से समूह, नेतृत्वकारी दल के हाथों में केन्द्रित होना। 2) इसी से जुड़ा है मजदूरों के कदमों का सीमित रहना, सिकुड़े रहना। आमतौर पर संघर्ष के दौरान भी अपनी फैक्ट्री के दायरे को मजदूर नहीं तोड़ते, अपनी फैक्ट्री के बारे में ही सोचते हैं। 3) तीसरा कारण है समय के साथ मजदूरों का बिखर जाना। यह पहले और दूसरे कारणों का अनिवार्य परिणाम होता है।

इस मूल्यांकन की परख के लिये कुछ प्रमुख घटनाक्रमों पर निगाह डालते हैं -

क) गेडोर-झालानी टूल्स फरीदाबाद : यहां इस कम्पनी के तीन प्लान्ट हैं और कुन्डली, जालना तथा औरंगाबाद में एक-एक प्लान्ट है। जर्मनी स्थित इसके तीन प्लान्ट 1985-86 में बन्द हो गये। यह कम्पनी हेन्ड टूल्स बनाती है और इसका उत्पादन कई देशों में बिकता है।

1973 के बाद एग्रीमेंटों में इन्सिस्टिव स्कीमों द्वारा यहां लगातार प्रोडक्शन में तेज वृद्धि हुई और यह सिलसिला 1980 तक चला। 1982 आते-आते मंडी की दिक्कतों और प्रतियोगिता में टिके रहने की आवश्यकता ने आटोमेशन और 3500 मजदूरों में से 1500 मजदूरों की छंटनी करना मैनेजमेंट के लिये जरूरी बना दिया। छंटनी का घटनाक्रम इस प्रकार रहा :

- नेतृत्व ने संकट की बात की और 600 मजदूरों की छंटनी अथवा 25 प्रतिशत वेतन में कटौती अथवा 6 महीनों के लिये आधे वेतन पर स्पेशल लीव पर

जाने, इनमें से एक को चुनने के लिये मजदूरों से कहा। वरकरी ने तीनों ही बातों को ठुकरा दिया।

● कुछ मजदूरों के मुखर विरोध पर मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि आटोमेशन मजदूरों के स्वास्थ्य के लिये किया जा रहा था और मजदूरों की छंटनी की मैनेजमेंट की कोई मन्शा नहीं थी।

● कुछ समय की चुप्पी के बाद मैनेजमेंट ने वेतन में देरी, बोनस पर लफड़ा और ले आफ की घोषणा की। तब नेतृत्व ने टूल डाउन स्ट्राइक की कॉल दी। फरवरी-मार्च 1983 की उस टूल डाउन स्ट्राइक को समाप्त करने की एग्रीमेंट को मजदूरों ने जब दो बार ठुकरा दिया तब नेतृत्व स्वयं हड़ताल-तोड़क बना। मजदूरों ने नेताओं को पीट कर भगा दिया।

● संघर्ष समिति बना कर अपना आन्दोलन स्वयं चलाने की बजाय मजदूरों ने नये नेताओं को आन्दोलन की बागडोर सौंप दी। नया नेतृत्व पुरानी एग्रीमेंट ही लाया और आम सभा में उस पर विचार किये बिना मजदूरों ने उसे स्वीकार कर लिया।

● छंटनी का मामला लटकते जाने पर मैनेजमेंट ने एक प्लान्ट में तालाबन्दी की। एक नई नेता मन्डली लाई गई और प्लान्टों के अन्दर व बाहर मार-पीट के जरिये मजदूरों से इस्तीफे लिखवाने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री के अन्दर चौकी बनाई।

नेताओं पर निर्भरता और फैक्ट्री के दायरे में बन्ध जाने ने मजदूरों को आहिस्ता-आहिस्ता बेबस व प्रतिरोध में स्वयं कदम उठाने में अक्षम बना दिया था।

ख) बम्बई स्थित कपड़ा उद्योग : 1982 में यहां 60 कपड़ा मिलों में ढाई लाख मजदूर काम करते थे। कपड़े से गोदाम टसाटस भर गये थे, मजदूरों में असन्तोष बढ़ रहा था तथा बड़े पैमाने पर छंटनी मैनेजमेंटों और सट्टा बाजार के एजेन्डा पर थी। संघर्ष के जज्बे के साथ-साथ लड़ाकू नेता की चाह ने कपड़ा मजदूरों में जोर पकड़ा। बम्बई के विशाल इंजिनियरिंग और दवाई उद्योगों में लड़ाकू नेता की छवि वाले डॉक्टर दत्ता सामन्त की एग्रीमेंटों के दौरान मैनेजमेंटों से दादागिरी के किस्से लोकगाथाओं का रूप ले रहे थे। कपड़ा मजदूरों के नेताओं ने दत्ता सामन्त को अपना एकछत्र नेता घोषित किया और 60 मिलों के ढाई लाख मजदूरों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया।

● दत्ता सामन्त के हड़ताल के आह्वान पर 60 मिलों का चक्का जाम हो गया।

● बम्बई क्षेत्र के इंजिनियरिंग व दवाई उद्योगों के मजदूरों ने दत्ता सामन्त के आदेश पर करोड़ों रुपये कपड़ा मजदूरों को सहायता के नाम पर दिये। दत्ता सामन्त ने हड़ताल में शामिल होने का आदेश नहीं दिया इसलिये इंजिनियरिंग व दवाई मजदूर शान्तिपूर्वक अपनी-अपनी फैक्ट्रियों में काम करते रहे।

● दत्ता सामन्त के आदेश पर बड़ी संख्या में कपड़ा मजदूर अपने गांवों को चले गये ताकि किसी प्रकार गुजर-बसर कर सकें।

● जो कपड़ा मजदूर बम्बई में रह गये थे वह दत्ता सामन्त के आदेश पर दस-बीस दिन में एक बार भेदान में विशाल भीड़ बन कर दत्ता सामन्त के भाषण सुनने पहुँचते थे।

● दत्ता सामन्त ने रोकने का आदेश नहीं दिया था इसलिये मजदूरों ने गोदामों से कपड़े की निकासी बेरोकटोक जारी रहने दी थी।

● अपने प्रियजनों के साथ स्वयं में ही दस लाख बनते कपड़ा मजदूरों ने रेल-रोड़-बन्दरगाह-हवाई अड्डों को जाम नहीं किया क्योंकि दत्ता सामन्त ने ऐसा आदेश नहीं दिया।

● उसी दौरान बम्बई में पुलिस कर्मचारियों ने बगावत कर दी थी। थानों तथा हथियारों पर कर्मचारियों ने कब्जा कर लिया था और पुलिस अफसर भाग खड़े हुये थे। दत्ता सामन्त ने आदेश नहीं दिया इसलिये कपड़ा मजदूरों की तरफ से पत्ता भी नहीं खड़का और जीपों पर तोपें लाद कर फौज ने पुलिस कर्मचारियों की बगावत को कुचल दिया था।

नेतृत्व पर निर्भरता, अत्याधिक निर्भरता ने मजदूरों को बेबस और प्रतिरोध के कदम स्वयं उठाने में अक्षम बना दिया था। नब्बे हजार कपड़ा मजदूरों की छंटनी हुई और शान्ति से मिलें चलने लगी।

ग) पोलैंड में मजदूर उभार : 1980 में पोलैंड में खाने-पीने की चीजों के भाव बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ मजदूरों की हड़तालों की लहर ने बगावत की शक्ल ले ली थी और तब मजदूरों को दबाने के लिये पोलैंड में फौजी शासन लागू किया गया था। 1988 में 'आर्थिक सुधार योजना' के नाम पर पोलैंड की फौजी सरकार ने आम जरूरत की चीजों के भाव औसतन 45 प्रतिशत बढ़ाये। इसके खिलाफ उठे चौतरफा हड़तालों के बवंडर ने फौजी सरकार को झकझोर दिया। हड़तालों के दौरान "दुनियाँ के भूखो, एक हो!" और "पोलैंड बचाओ!" के परस्पर विरोधी नारे लग रहे थे। "पोलैंड बचाओ" नारे लगाने में अगुआ सोलिडैरिटी संगठन ने शीघ्र ही हड़तालों पर अपना नेतृत्व स्थापित किया। सोलिडैरिटी नेता लेक वालेसा आगे चल कर पोलैंड का राष्ट्रपति बना और फौज उसकी भी गारद बनी।

मजदूर नेता के राष्ट्रपति बन जाने के बाद पोलैंड में मजदूरों पर हमले पहले की ही तरह जारी हैं। पोलैंड में काम कर रही एक महिला मजदूर इस पर कहती है, "हम तीन शिफ्टों में काम करती हैं। आठ घन्टे की नाइट शिफ्ट के बाद सुबह ग्यारह बजे तक राशन की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। फिर खाना बनाना और दो घन्टे सोने के बाद वापस काम पर... टी वी पर शाम को भाव बढ़ाने की नित नई घोषणायें की जाती हैं। काम करते वक्त हम एक-दूसरे से भावों पर चर्चा करती हैं और गालियाँ देती हैं। हमें कहा जाता है कि हड़ताल की वजह से प्रोडक्शन गिरेगा और हमें व फैक्ट्री, दोनों को नुकसान होगा। जलूसों से कोई खास फरक नहीं पड़ता पर जलूस सरकार को कम से कम इतना तो याद दिला ही देते हैं कि मजदूर वर्ग है।"

स्पष्ट है कि नेतृत्व पर निर्भरता मजदूरों को धकेल कर दलदल में पहुँचा देती है। और, सीमित होने, सिकुड़ जाने का अर्थ फैक्ट्री के दायरे में कैद होना ही नहीं है बल्कि उत्पादन की शाखा और देश के दायरों में कैद हो जाना भी है।

★ ★ ★

विदूषक : मायूस हो गये? कहीं यह तो नहीं सोचने लगे कि करने से होता ही क्या है?

कहीं-कहीं संघर्ष की तीव्रता में जोश-खरोश में मजदूर ऐसे कदम उठाते हैं जो सम्पूर्ण मजदूर वर्ग के लिये आन्दोलन की नई राहें-नई दिशायें-नये धरातल तथा ताकत के नये आधार इंगित करते हैं। ऐसे आन्दोलनों की जानकारी तथा उनके मतलब पर मनन करके हम अपनी समझ और आन्दोलन करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं।

क) कानपुर में दस कपड़ा मिलों के 35 हजार मजदूरों, उनके प्रियजनों और समर्थकों ने 22 फरवरी 1989 को छंटनी रोकने के लिये दिल्ली-कलकत्ता मेन रेल लाइन जाम कर दी। रोज अपनी-अपनी शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद दस हजार मजदूर आ कर रेल की पटरियों पर बैठने लगे। एक शिफ्ट के मजदूरों के आने के बाद ही दूसरी शिफ्ट के मजदूर पटरियों से उठते थे। सरकार द्वारा छंटनी का आदेश वापस लेने के बाद ही मजदूरों ने 27 फरवरी को रेल जाम खल किया।

27 फरवरी 1989 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, "कपड़ा मजदूरों का रेल रोको आन्दोलन कई मायनों में बेजोड़ है। मजदूर खुद लीडर बन गये हैं और स्थापित ट्रेड यूनियनों के नेता किनारों पर खड़े हैं।"

ख) इटली में क्रोटोन नगर स्थित एनिकेम केमिकल फैक्ट्री के 500 मजदूरों ने छंटनी रोकने के लिये 6 सितम्बर 1993 को फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्री खाली करवाने के लिये पुलिस के हमले को विफल करने के लिये मजदूरों ने फोसफोरस भरे ड्रम फैक्ट्री गेट को आती सड़क पर बिछा कर उनमें आग लगा दी। एनिकेम मजदूरों, उनके प्रियजनों और समर्थकों ने क्रोटोन रेलवे स्टेशन पर कब्जा करके रेल लाइन जाम कर दी और क्रोटोन हो कर गुजरती मुख्य सड़क पर केमिकल भरे ड्रम बिछा कर उसे भी जाम कर दिया। इटली सरकार द्वारा छंटनी नहीं करने की घोषणा के बाद ही यह मामला शान्त हुआ।

ग) फ्रान्स में एयरलाइन्स मजदूरों का तीखा संघर्ष : 12 अक्टूबर 1993 को एयर फ्रान्स के 4000 ग्राउन्ड स्टाफ वरकरी ने छंटनी और वेतन में कटीती रोकने के लिये हड़ताल शुरू की। 18 अक्टूबर को लीडरों की बातें अनसुनी करके हड़ताली मजदूरों ने पेरिस के दो प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ान-पड़ियों पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने ऑसू गैस के गोलों और ठन्डे पानी की तोपों से मजदूरों पर वार कर तीन घन्टे की जहोजहद के पश्चात उड़ान-पड़ियां खाली करवाई। 19 अक्टूबर को मजदूर तैयार हो कर आये। ऑसू गैस से मुकाबले के लिये मजदूर गैस मास्क पहन कर आये और उड़ान-पड़ियों पर जगह-जगह जलते टायरों के ढेर लगा दिये। हमला कर रही पुलिस से हड़ताली मजदूरों ने आँख-मिचौनी भी खेली और कई पुलिस वालों को हवाई अड्डे के एक गोदाम में बन्द कर दिया। एयर फ्रान्स को 500 उड़ानें रद्द करनी पड़ी जिससे व्यापक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभावकारी चोट पड़ने लगी। विश्व की राजधानियों और सट्टा बाजारों में हड़कम्प मच गई। फ्रान्स के प्रधान मन्त्री ने हड़ताली मजदूरों से देश का ख्याल करने की अपील की। इस पर अगले दिन हड़ताली मजदूरों ने पेरिस हवाई अड्डों को जाती सड़कों को भी जाम कर दिया। पेरिस के बाहर हड़ताल फैलने के बने आसार और ग्राउन्ड स्टाफ की हड़ताल में उड़ान वरकरी के शामिल होने के फैसले से घबरा कर फ्रान्स सरकार ने छंटनी व वेतन में कटीती के अपने फैसले वापस ले लिये।

विभिन्न उद्योगों की परस्पर निर्भरता, विभिन्न क्षेत्रों की अन्तरनिर्भरता, बढ़ती विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरता मजदूरों के लिये, मजदूर वर्ग के लिये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। परम्परागत हड़ताले अब बेशक नाकारा साबित हो रही हैं पर सही निशानों पर थोड़े से मजदूरों द्वारा भी की गई चोट आज विश्व-अर्थव्यवस्था तक पर गम्भीर असर डाल सकती है। मजदूरों को यह हालात आज कितनी ज्यादा ताकत प्रदान

कर सकते हैं यह बात जब-तब आन्दोलनों में उभरती है पर इसकी पहचान मजदूरों ने ठीक से अभी नहीं की है।

● 1989 में इंग्लैंड के बर्मिंघम नगर में चन्द कम्प्यूटर आपरेटरों की हड़ताल ने समस्त स्थानीय टैक्स वसूली पर पूर्ण विराम लगा दिया।

● 1991 में रेनाल्ड कार कम्पनी के इंजन प्लान्ट में 200 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इससे रेनाल्ड कम्पनी की विभिन्न फैक्ट्रियों में काम ठप्प हो गया।

● 24 जून 1992 को अमरीका में एक रेलवे कम्पनी के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस पर चालीस अन्य रेलवे कम्पनियों ने तालाबन्दी कर दी। इससे विश्व की विशालतम कम्पनी, जनरल मोटर्स तक में 48 घंटों में प्रोडक्शन जाम होने की नीवत आ गई। अमरीका के राष्ट्रपति ने हालात से निपटने के लिये इमरजेंसी लागू की।

● 26 अक्टूबर 1993 को बाटा फरीदाबाद में कार्यस्थल पर असहनीय गरमी के विरोध में 16 मजदूरों ने दिन के डेढ़ बजे काम बन्द कर दिया। इससे फैक्ट्री में प्रोडक्शन जाम हो गया।

आधुनिक टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेन सिस्टम की ही तरह प्रोडक्शन यूनिटों के बीच भी चेन सिस्टम बना दिये हैं। जस्ट-इन-टाइम नाम से पुकारी जा रही इस प्रणाली में मजदूरों के छोटे-छोटे समूहों तक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

★ ★ ★

उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर बंगाल में हावड़ा जिले में स्थित कनोड़िया जूट मिल के घटनाक्रम पर विचार करें :

● 1984 में बंगाल की जूट मिलों में ढाई लाख मजदूर काम करते थे। प्रोडक्शन बढ़ता रहा, वर्क लोड बढ़ता रहा और मजदूर कम होते रहे - 1992 में जूट मिलों में एक लाख चालीस हजार मजदूर ही रह गये थे। जूट मिलों में तालाबन्दी एक आम बात रही है। बीमार घोषित मिलों में वेतन कटौती आम है क्योंकि बैंकों द्वारा कर्ज देने की यह एक अनिवार्य शर्त होती है। कई जूट मिलों में तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम करने के एग्रीमेंट हुये हैं।

● कनोड़िया जूट मिल बीमार है। BIFR की शर्तों के अनुसार मजदूरों के वेतन में कटौती की जा रही थी।

● विद्यमान पांच यूनियनों से किनारा करके मजदूरों ने एक नई यूनियन बनाई और वेतन में कटौती का विरोध किया। इस पर मैनेजमेंट ने फैक्ट्री में तालाबन्दी कर दी।

● तालाबन्दी के खिलाफ फैक्ट्री गेट पर भूख हड़ताल का सिलसिला चला। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा घन्टा एकत्र करना संग-संग चले।

● तालाबन्दी को महीने-भर से ऊपर हो गया तब 19 दिसम्बर 1993 को एक हजार मजदूरों ने गेट पर लगा ताला तोड़ कर फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया।

● सांस्कृतिक कर्मियों, कलकत्ता के कालेज छात्रों और कई अन्य लोगों ने मजदूरों के इस कदम का समर्थन किया।

● बड़े अंग्रेजी और बंगला अखबारों में इस घटनाक्रम पर अन्य जूट मिलों, इंजिनियरिंग उद्योग और अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों की कोई प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिली है।

● नेतृत्व ने प्रोडक्शन और मार्केटिंग को लक्ष्य घोषित कर दिया है और मजदूरों का ध्यान मुख्यतः इन पर केन्द्रित है।

● अदालती लड़ाई और सरकार तथा मैनेजमेंट से नेगोसियेशन में नेतृत्व के कौशल पर मजदूर आस लगाये बैठे हैं।

विदूषक : हाल ही में कारखाने पे कब्जा हुआ है

कहीं पर,
फौरन फैक्स पहुंचता है कहीं और
उमड़ सकती है कहीं और हड़ताल
रेल, रास्ते रोके जा सकते हैं
हजारों निकल पड़े हैं सड़कों पर
दुनियाँ बदल रही है
अब तो, यहां-वहां, चारों दिशा
अपने शहर के चौराहों पर विराजमान हैं
फैक्स और फोन की दुकानों ने यह देस-परदेस के भेद
को कहाँ छोड़ रखा है,
मेरी-तुम्हारी फैक्ट्री की दीवारें कैसे खड़ी हैं अब तक
जबकि हम आज यहां, और कल वहां खटते हैं।
कहाँ नहीं जाते मजदूर, कहाँ नहीं बसते
हवाई अड्डों, बन्दरगाहों, सीमाओं पर खड़ी कतारें
हर हार-जीत, हर तजुरबे की खबर
यहाँ-वहाँ फैला रही है
दुनियाँ बदल सकती है
सुनो, हाल ही में हवाई अड्डे पे, कहीं कारखाने पे
कब्जा हुआ है,
अब दुनियाँ की बारी है
दुनियाँ बदल रही है

विदूषक जी, जरा इतना भी मत उछलिये कि खतरे ही आपकी आँखों से ओझल हो जायें। मार-काट, खून-खराबे की खुली वकालत करने वालों को आजकल फिर से आदर मिलने लगा है। नित नये-नये दुश्मन गढ़े जा रहे हैं और उनके सफाये के आह्वान किये जा रहे हैं।

हम ऐसे दौर में पहुँच गये लगते हैं जहाँ आशायें और निराशायें दोनों प्रबल हो रही हैं। कौन किसको चित्त करेगी इससे हमारा भविष्य निर्धारित होगा। इस माहौल ने व्यक्ति के हस्तक्षेप का, हमारे सामुहिक सचेत कदमों का महत्व बड़ा दिया है।

सम्पादकीय

फरीदाबाद मजदूर समाचार की नई सीरीज को छपते पाँच वर्ष से ऊपर हो गये हैं। इस दौरान अखबार का थोड़ा-सा विकास ही हुआ है। रिपोर्टें, अनुभवों, टीका-टिप्पणी के रूप में अखबार के प्रकाशन में थोड़े-से लोग ही सक्रिय रहे हैं, बड़ी संख्या में मजदूरों की भागीदारी बहुत-ही कम रही है।

कारखानों में जारी टकरावों, समाज में जारी द्वन्द्वों की जानकारी-जाँच परख-विश्लेषण-समझ हासिल करने के प्रयासों के नतीजे इस अखबार की सामग्री होते हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच इन बातों की चर्चा में यह अखबार भी एक जरिया बने। मैनेजमेंटों के खिलाफ मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ाना, अमानवीय व मानवद्रोही वर्तमान के खिलाफ विश्व मानवीय विकल्प के उभरने में हाथ बँटाना इस अखबार से जुड़े हम लोगों का लक्ष्य है।

लेकिन हमारा नीरसपन तथा छोटापन हमारे लिये काफी बड़ी बाधाएँ हैं। हम अखबार को जीवन्त-रोचक-रंगीन बनाना चाहते हैं। हजार-दो हजार की बजाय हम इसे बड़ी संख्या में छपता देखना चाहते हैं। महीने में एक बार की जगह हम अखबार को पाक्षिक-साप्ताहिक-दैनिक छापना चाहते हैं। आपकी भागीदारी हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिये जरूरी है।

दिसम्बर 93 अंक की चार हजार प्रतियाँ छापी थी और जनवरी 94 अंक दस हजार प्रतियों का है। हमें आशा है कि रफ्तार को बढ़ाने में पाठकों का सहयोग हमें मिलेगा।

अफ्रीका-यूरोप-एशिया-उत्तरी व दक्षिणी अमरीका-आस्ट्रेलिया के छह अरब लोगों के सचेत-सामुहिक-मुखर प्रयासों में हम सब के उज्ज्वल भविष्य की कुँजी है। समय व स्थान की प्राकृतिक बाधाओं तथा देश-धर्म-जाति-भाषा की सामाजिक दीवारों को पार करना, लोगों के बीच आदान-प्रदानों का बढ़ना, इस सिलसिले में बुनियादी महत्व की जरूरत है। विभिन्न स्थानों से प्रकाशित, बड़ी संख्या में छपते मजदूरों के अखबार इस काम में उल्लेखनीय रोल अदा कर सकते हैं।

— — — फ . म . स . प्रकाशक समूह

दिसम्बर 93 अंक से कुछ लोग इस कदर प्रभावित हुये कि बैठते-बैठते अखबार पाँचवें दिन, 11 दिसम्बर को सुबह जब एस्कोर्ट्स के राजदूत प्लान्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तब पाँच-सात के एक ग्रुप ने धमकियाँ दी और छीन कर पचास-साठ अखबार फाड़ डले। ऐसी प्रतिक्रियायें भी हमारे लिये उपयोगी हैं लेकिन... हमारे लिये अधिक अर्थपूर्ण होगा उन लोगों द्वारा अखबार का सालाना ग्राहक बनना जो कि नियमित तौर पर इसमें प्रकाशित सामग्री पढ़ना चाहते हैं। स्वयं आ कर अथवा मनीआर्डर द्वारा 15 रुपये इस पते पर भेजें — सम्पादक फ म स, मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद - 121001